Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

13th October 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

13th October 2022

1. - G7 का विवरण: 3

(i) G7 क्या है? 3

(ii) G7 में प्रतिभागी: 3

(iii) G-7 में भारत की भागीदारी: 3

(iv) निष्कर्ष: 4

2. - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में: 5

(i) पार्श्वभूमि: 5

(ii) आईएमएफ के लक्ष्य: 5

(iii) प्रशासनिक संगठन: 5

3. - सूचना का अधिकार अधिनियम का विवरण: 6

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005: 6

(ii) आरटीआई के कार्यान्वयन के खिलाफ तर्क: 6

(iii) चुनौतियां: 7

(iv) अगले कदम: 7

4. - भारत में 5 जी सेक्टर के बारे में: 8

(i) कैसे काम करती है 5G तकनीक? 8

(ii) चीजें 1G से 5G में कैसे बदलीं? 8

(iii) 5G तकनीक के अनुप्रयोग और लाभ: 8

(iv) चुनौतियां: 9

(v) आगे बढ़ते हुए: 9

(vi) निष्कर्ष: 10

संपादकीय विश्लेषण 11

1. भारत में जनसंख्या नियंत्रण: 11

(i) जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत: 11

(ii) भारत में जनसंख्या प्रबंधन के मुद्दे: 11

(iii) कैसे चलते रहें: 12

(iv) निष्कर्ष: 12

2. भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतें: 13

(i) युवा: 13

(ii) सबसे आम तकनीक: 13

(iii) अन्य घटक: 13

(iv) आत्महत्या बनाम आत्महत्या के प्रयास: 13

(v) आख़िर आत्महत्या क्या है? 13

(vi) उपचार और उपचार: 13

(vii) भारत सरकार के कार्यों में शामिल हैं: 14

(viii) उद्देश्य: 15

1. - G7 का विवरण:

GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

➢ **संदर्भ:**

- G7 शिखर सम्मेलन पिछले मिसाइल हमले की निंदा करने वाला था कि कीव के सहयोगियों को मास्को की हताशा का संकेत माना जाता था। मंगलवार को रूस ने दावा किया कि उसने कुछ घंटे पहले यूक्रेन पर "सामूहिक" हमले शुरू कर दिए थे।

G7 क्या है?

- सात का समूह स्थापित लोकतंत्रों (G7) का एक ढीला गठबंधन है।
- वैश्विक आर्थिक शासन, ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर बात करने के लिए समूह की वर्ष में एक बार बैठक होती है।
- G7 बनाने वाले देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और जापान हैं।
- भारत अन्य G7 देशों में से प्रत्येक के साथ G20 के सदस्यों में से एक है।
- G7 में एक लिखित संविधान के साथ-साथ एक निश्चित मुख्यालय का अभाव है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं।

G7 में प्रतिभागी:

- विशेष अतिथि के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बियारिट्ज़ में 45 वें जी -7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह इससे पहले पांच जी -7 सभाओं की यात्रा कर चुके हैं।
- भारत, चीन और ब्राजील में हाल के तीव्र आर्थिक विकास ने वैश्विक स्तर पर जी-7 समूह के महत्व को कम कर दिया है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसके हिस्से को लगातार कम किया है। इस स्थिति में समूह के बचने की संभावना कम है। इस स्थिति में, भारत ने G7 राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

G-7 में भारत की भागीदारी:

- भारत और यूरोपीय संघ डेटा सुरक्षा पर असहमत हैं, जिसका जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक माहौल पर प्रभाव पड़ता है। G-7 समूह भारत और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत के लिए एक अलग मंच प्रदान करेगा।
- इन तीनों देशों का अंतरराष्ट्रीय समुदाय में प्रभाव है क्योंकि ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद है।
- यदि रूस करता है तो भारत शामिल होने में अपने लंबे समय के दोस्त का समर्थन करने में सक्षम होगा।
- इस संगठन के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लोकतंत्रीकरण जैसी अवधारणाओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में पेश कर सकता है।

- इन देशों और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भारतीय जनता के लिए रोजगार के अवसरों की संख्या में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

- भारत से जी-7 की बैठकों में भाग लेने का अनुरोध और सदस्यता के लिए जोर उसकी बढ़ती शक्ति के स्पष्ट संकेत हैं। G-7 को दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रतीक बनाने के लिए बनाया गया था, और भारत वर्तमान में दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की बढ़ती शक्ति का एक और संकेत भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तावित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पसंद है। जी-7 के सदस्यों को अब समूह के विस्तार पर ध्यान देना है।

- ***स्रोत→ हिन्दू***

GURU DEEKSHAA IAS

2. - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में:

GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

➢ **संदर्भ:**

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, आने वाले वर्ष में एक वैश्विक मंदी आएगी, जो भारत को भी प्रभावित करेगी, रूस और यूक्रेन में संघर्ष के परिणामस्वरूप, विश्व स्तर पर मौद्रिक नीति को कड़ा करना, दशकों में सबसे बड़ी मुद्रास्फीति, और देश के सुस्त प्रभावों के कारण। महामारी (आईएमएफ)।

पार्श्वभूमि:

- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने 1944 में आईएमएफ के निर्माण का नेतृत्व किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), जिसकी स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को हुई थी, में वर्तमान में 189 देश शामिल हैं।
- वाशिंगटन, डीसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वैश्विक वाणिज्य, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों (आईएमएफ) में से एक है।
- महामंदी के दौरान वैश्विक मौद्रिक सहयोग के पतन की प्रतिक्रिया में, आईएमएफ की स्थापना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर गरीबी को खत्म करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का निर्माण हुआ।
- बैठक, जिसमें युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा हुई, ने लगभग 45 आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों को आकर्षित किया।

आईएमएफ के लक्ष्य:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा
- मजबूत रोजगार वृद्धि और एक विश्वसनीय आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करें।

प्रशासनिक संगठन:

- IMF को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है, जो इसका मूल संगठन भी है।
- IMF के प्रबंध निदेशक को कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना जाता है और यह पांच साल के कार्यकाल के लिए कार्य करता है।
- कार्यकारी बोर्ड, मंत्रिस्तरीय समितियाँ और बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) शामिल हैं।

- ***स्रोत→ हिन्दू***

3. - सूचना का अधिकार अधिनियम का विवरण:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➢ **संदर्भ:**

- भारत द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पारित करने के लगभग 17 साल बाद, देश भर में 26 सूचना आयोगों के पास अभी भी लगभग 3.15 लाख अनसुलझी शिकायतें या अपीलें हैं, जो साबित करती हैं कि देश की खुलेपन की तथाकथित प्रणाली अभी भी एक भ्रम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005:

- सार्वजनिक प्राधिकरण संगठन और प्रबंधन के कई पहलू हैं जिन्हें खुले तौर पर और ईमानदारी से प्रकट किया जाना चाहिए। यह उनके संगठनात्मक ढांचे, परिचालन प्रक्रियाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ वित्तीय जानकारी पर विवरण प्रदान करता है।
- स्व-सरकार का एक निकाय जिसे "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में जाना जाता है, वह है जिसे संविधान, एक क़ानून या कानूनी डिक्री के अनुरूप स्थापित किया गया था।
- मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और नियामक उनमें से कुछ हैं।
- इसमें कोई भी व्यवसाय शामिल है जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व, प्रबंधन या वित्तपोषित हैं और साथ ही ऐसे संगठन भी शामिल हैं जो सरकार के पैसे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं।
- सरकारों को आम तौर पर अप्रत्याशित और सक्रिय तरीके से जानकारी जारी करने के लिए विनियमन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।
- नागरिक किसी भी अनुपलब्ध जानकारी को स्पष्ट पत्राचार, ईमेल, ऑनलाइन आवेदन, या दोनों के माध्यम से एक छोटे से शुल्क के लिए खरीद सकते हैं।
- यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों में जवाबदेही और खुलेपन को बढ़ावा देने के इरादे से पारित किया गया था।

आरटीआई के कार्यान्वयन के खिलाफ तर्क:

- अक्टूबर 2021 में भारत में आरटीआई अधिनियम की 16वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, सतरक नागरिक संगठन ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके देश भर में सूचना आयोगों की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन विकसित किया है।
- रिपोर्ट का शीर्षक 2020-21 के लिए सूचना आयोगों का रिपोर्ट कार्ड है।
- जांच से पता चलता है कि सूचना आयुक्तों की अधिक संख्या के कारण आरटीआई कानून के सफल कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।

चुनौतियां:

- विचार यह है कि व्यर्थ या अप्रिय अनुरोधों की भारी मात्रा अक्सर इस नौकरशाही दृष्टिकोण को सही ठहराती है। सच्चाई यह है कि ये समस्याएं कुल मिलाकर केवल 4% अपीलों में ही उत्पन्न होती हैं और इन्हें सापेक्ष आसानी से हल किया जा सकता है।
- राज्य सूचना आयोगों के साथ समस्याएं
- संवेदनशील जानकारी निषिद्ध है, कुछ अभी भी प्रमुखों के बिना कार्य करते हैं, और पद अभी भी खुले हैं।
- पीआईओ: कई बार, पीआईओ की बहादुरी अद्भुत होती है। मध्य प्रदेश के एक सूचना आयुक्त ने एक पीआईओ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जब उन्होंने आयोग की बैठकों और एसआईसी के आदेशों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 38 समन की अनदेखी की।
- किसी भी महत्वपूर्ण आरटीआई अनुरोध या कई सरकारी विभागों को शामिल करने के लिए उच्च अधिकारियों को कदम उठाने की आवश्यकता होती है; फिर भी, निचले रैंक के पीआईओ नियमित रूप से सुनवाई में शामिल होते हैं और किसी काम के नहीं होते हैं।

अगले कदम:

- प्रभावी होने के लिए, आरटीआई प्रणाली को एक मजबूत राजनीतिक आधार की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए कठोर प्रशिक्षण आयोजित करने से, दुनिया में मौजूदा सबसे मजबूत सूचना कानूनों में से एक और अधिक सख्त हो सकता है।
- संघीय और राज्य सूचना आयुक्तों दोनों के लिए एक आचार संहिता आवश्यक है।
- जनता और वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट रूप से आयुक्तों से दूर रखा जाना चाहिए।
- यह आम जनता, नागरिक समाज, मीडिया, अदालतों और अंततः आयुक्तों पर निर्भर है कि वे आरटीआई प्रणाली का मनोबल बढ़ाएं।

- *स्रोत→ हिन्दू*

4. - भारत में 5 जी सेक्टर के बारे में:

GS III

विषय→विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे

➢ **संदर्भ:**

- 5G सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन के मालिक होने के बावजूद, कई उपयोगकर्ता इसके लॉन्च के दो सप्ताह से अधिक समय तक अल्ट्रा-हाई स्पीड नेटवर्क का उपयोग करने में असमर्थ हैं। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने और रोल-आउट को तेज करने के लिए दूरसंचार कंपनियों और फोन निर्माताओं का एक सम्मेलन बुलाया है।

कैसे काम करती है 5G तकनीक?

- बेतार संचार प्रौद्योगिकी की पांचवीं पीढ़ी (5G) अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, रेडियो आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला और 10 Gbps तक की गति प्रदान करती है (4G से 20 गुना)।
- IEEE 802.11ac ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग मानक इसका आधार है। हालांकि, कोई पूर्व निर्धारित आधिकारिक मानक नहीं है।
- भविष्य के 5G मानक को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा विकसित किया जाएगा।

चीजें 1G से 5G में कैसे बदलीं?

- 1G: शुरुआत में 1980 के दशक में पेश किया गया था। एनालॉग रेडियो तरंगों का उपयोग केवल वॉयस कॉल करने के लिए किया जा सकता था।
- 2G, जो डिजिटल रेडियो प्रसारणों को नियोजित करता है और 64 Kbps के भाषण और डेटा ट्रैफ़िक को संभाल सकता है, पहली बार 1990 के दशक में पेश किया गया था।
- 3जी को पहली बार 2000 के दशक में पेश किया गया था। यह 1 एमबीपीएस से 2 एमबीपीएस तक की गति से डिजीटल भाषण, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित कर सकता है।
- 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक की पीक स्पीड के साथ, 4जी 3डी वर्चुअल रियलिटी को भी व्यावहारिक बनाता है।
- 1Gbps से अधिक की गति के साथ, 5G ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु को जोड़ सकता है।

5G तकनीक के अनुप्रयोग और लाभ:

- 5G की तेज़ गति के साथ, HD वीडियो, मूवी, गेम और अन्य हाई-बैंडविड्थ मनोरंजन डाउनलोड करना संभव है।
- यह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उच्च गति डेटा सेवाओं के उपयोग को सक्षम बनाता है।
- आवेदन संभव हैं जो वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना आसान बना देगा। यह ड्राइवर रहित कारों को क्लाउड सेवाओं से संगीत अपडेट,

सॉफ़्टवेयर अपडेट और नेविगेशनल डेटा को तेज़ी से डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करना आसान होगा ताकि वे एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकें, जिससे यातायात और कार दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।

- यह स्मार्ट उपकरणों के बीच कुशल डेटा ट्रांसमिशन को संभव बनाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाएगा।
- डिजिटल विस्तार को गति वृद्धि से बढ़ावा मिलता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाता है और नई नौकरियां जोड़ता है।

चुनौतियां:

- 5G द्वारा पेश किए गए अधिक से अधिक हमले की सतह के कारण, जो लाखों या शायद अरबों अतिरिक्त जुड़े उपकरणों द्वारा संभव बनाया गया है, बड़े और जोखिम भरे हमले बोधगम्य हैं। मौजूदा इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर की खामियां समय के साथ और बदतर होती जाएंगी। 5G के साथ अधिक परिष्कृत बॉटनेट, गोपनीयता उल्लंघन और तेज डेटा निष्कर्षण की उच्च संभावना मौजूद है।
- जैसे-जैसे इसका विस्तार होता है IoT की चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। IoT डिवाइस स्वाभाविक रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं क्योंकि पूरी डिज़ाइन प्रक्रिया में सुरक्षा की अक्सर अनदेखी की जाती है। कंपनी नेटवर्क पर, प्रत्येक असुरक्षित IoT डिवाइस घुसपैठ के जोखिम को बढ़ा देता है।
- नेटवर्क दृश्यता का नुकसान हमारे नेटवर्क का विस्तार 5G के साथ होगा, जिससे यह बढ़ेगा कि मोबाइल उपयोगकर्ता और डिवाइस कितनी कुशलता से उनका उपयोग कर सकते हैं। नतीजतन, अधिक नेटवर्क ट्रैफ़िक को संभालना आवश्यक होगा। हालांकि, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज (एसएएसई) जैसे मजबूत वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) सुरक्षा समाधान के बिना, उद्यम विसंगतियों या हमलों का पता लगाने के लिए आवश्यक नेटवर्क ट्रैफ़िक दृश्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ मदद करना 5G का समर्थन करने के लिए संचार प्रणाली की अंतर्निहित वास्तुकला को बदलना होगा। 5G का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह ज्यादा दूर तक डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। नतीजतन, 5जी तकनीक के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है।
- उपभोक्ता वित्तीय विवेक: 4G से 5G में बदलाव के लिए नवीनतम सेल्युलर तकनीक में अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो ग्राहकों के लिए महंगा है।
- फंड की कमी के कारण 5जी स्पेक्ट्रम के वितरण में देरी हो रही है। अपर्याप्त वित्त वाली व्यवहार्य दूरसंचार कंपनियों के उदाहरण भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हैं।

आगे बढ़ते हुए:

- भारत को मौके का फायदा उठाकर 5जी तकनीक का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। हमें अपने वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- इन डिज़ाइन और उत्पादन क्षमताओं की पेशकश करने वाले 5G स्टार्ट-अप का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, वायरलेस नेटवर्क का घनत्व, क्षमता और कवरेज सभी में बहुत सुधार होगा।

निष्कर्ष:

- भारत में 5G तकनीक की तैनाती से कंपनियों को वहां 5G उत्पाद बनाने और उत्पादन करने में मदद मिलेगी, जिससे 5G मानक में कुछ आवश्यक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का निर्माण होगा। भारत को जल्द से जल्द घरेलू दूरसंचार उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि स्थानीय कंपनियां घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

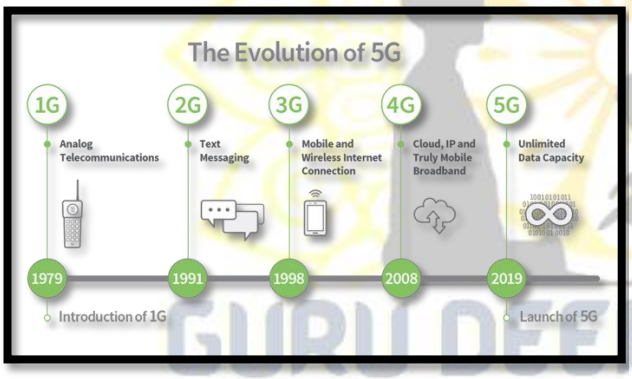

- *स्रोत→ हिन्दू*

संपादकीय विश्लेषण

1. भारत में जनसंख्या नियंत्रण:

जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत:

- अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत में, माल्थस ने भविष्यवाणी की कि जनसंख्या वृद्धि की दर खाद्य उत्पादन की दर (1798) से आगे निकल जाएगी।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि जबकि जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ी, भोजन की उपलब्धता एक अंकगणितीय अनुपात (ज्यामितीय वृद्धि) में अधिक धीमी गति से बढ़ी।
- जैसे-जैसे कृषि प्रौद्योगिकी उन्नत हुई और भारत जैसे देशों ने शुद्ध खाद्य अधिशेष का आनंद लिया, माल्थस अंततः गलत साबित हुआ।
- हार्वर्ड अर्थशास्त्री हार्वे लिबेंस्टीन के बिग-पुश थ्योरी के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि आम तौर पर कमाई में गिरावट का कारण बनती है।
- इस सिद्धांत का मुख्य आर्थिक कारण यह था कि कम प्रति व्यक्ति आय लोगों को पैसे बचाने से रोकेगी।
- अगर निवेश और बचत बराबर होते तो इसका मतलब होता कि अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है।

भारत में जनसंख्या प्रबंधन के मुद्दे:

- इस तथ्य के बावजूद कि इनमें से कई परिकल्पनाएं बेतहाशा झूठी निकलीं, फिर भी उन्होंने जनसंख्या अर्थशास्त्र की हमारी समझ में सुधार किया। इसके बाद के तर्क उन कारणों को प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा क्यों है।
- सभी जनसंख्या वृद्धि इंगित नहीं करती है कि अर्थव्यवस्था को परेशानी हो रही है। एक बड़ी आबादी का हमेशा अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित परिणाम जनसंख्या प्रबंधन पहल के परिणाम होंगे:
- सीधे शब्दों में कहें तो, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त काम नहीं होगा, देखभाल करने के लिए एक बड़ी, अनुत्पादक वरिष्ठ आबादी होगी, और पेंशन के भुगतान के लिए सरकारी खजाने में पर्याप्त पैसा नहीं होगा।
- नतीजतन, एक गैर-औद्योगिकीकरण होगा।
- जनसंख्या फैलाव कारक: जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने 1937 के व्याख्यान में इस विषय को कवर किया, जिसका शीर्षक था "एक घटती जनसंख्या के कुछ आर्थिक परिणाम।"
- उनकी प्रमुख चिंता यह थी कि उन जगहों पर निवेश की ज्यादा जरूरत नहीं थी जहां कंपनियों को घटते उपभोक्ता आधार को पूरा करना था।
- एक केस के रूप में चीन का अध्ययन करते हुए चीन ने 1980 के दशक में एक बच्चे की सीमा लागू की, लेकिन सीमा के परिणामस्वरूप, देश की आबादी बड़ी हो गई। नतीजतन, चीन ने अपने पिछले नियमों को छोड़ दिया और माता-पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- भारत में जनसंख्या प्रबंधन के मुद्दे को देश के धार्मिक विभाजनों द्वारा बदतर बना दिया गया है।
- जनसंख्या वृद्धि की भ्रांति आमतौर पर भारत में किसी विशेष अल्पसंख्यक को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से या आकस्मिक रूप से लागू की जाती है। जनसंख्या नियंत्रण योजना सामाजिक समरसता को प्रभावित करेगी।
- वंचित कुल प्रजनन दर (टीएफआर) से प्रभावित होते हैं, जो कम भाग्यशाली लोगों में अधिक होते हैं और आय में वृद्धि के रूप में गिरते हैं।

- इसलिए गरीबों को, जिन्हें इस तरह की सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, अंततः हकदारी पर आधारित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का परिणाम भुगतना पड़ेगा।
- पितृसत्ता: पुरुष संतान के लिए पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति उच्च प्रजनन दर का मुख्य कारण है।
- आरोपों के अनुसार, दो बच्चों की सीमा ने कन्या भ्रूण हत्या और अन्य लिंग आधारित अपराधों जैसे अपराधों को प्रोत्साहित किया, जिसका जनसंख्या के लिंग अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

कैसे चलते रहें:

- जनसांख्यिकीय लाभांश पर ध्यान दें: भारत को इसके बारे में चिंता करने के बजाय अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए।
- भारत अपने जनसंख्या लाभ का उपयोग करने और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक असाधारण स्थिति में है।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार, 2021 में भारत की जनसंख्या का 53.6% 29 वर्ष से कम आयु का होगा। भारत में 25% से अधिक लोग 14 वर्ष से कम आयु के हैं।
- हमारे नीति निर्माताओं को भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में चिंता करने के बजाय उसका उपयोग करने पर ध्यान देना अच्छा होगा।
- विकासशील कौशल सेट: आज भारत में युवाओं के पास हमेशा महानतम अवसरों तक पहुंच नहीं हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफी संरचनात्मक विसंगतियां हैं।
- यह युवा आबादी या तो अत्यधिक उत्पादक या अप्रभावी हो सकती है, जो उसके द्वारा विकसित कौशल सेट पर निर्भर करती है।
- महिलाओं पर ध्यान: पहले बच्चे के जन्म के समय प्रजनन दर और मां की उम्र दोनों ही महिलाओं में शिक्षा की मात्रा से प्रभावित होती हैं। शिक्षा समय से पहले जन्म और महिला बांझपन की व्यापकता को कम करती है।

निष्कर्ष:

- भारत जिस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसे देखते हुए अगले दो से तीन दशकों के दौरान प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी सकारात्मक है, इसलिए इसे धीमा करने का अवसर है। हालाँकि, हमारी जनसांख्यिकीय नीति में जनसंख्या ठहराव के दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

2. भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतें:

- पिछले 10 या इतने वर्षों में थोड़ी गिरावट के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों के लिए भारत की आत्महत्या दर अभी भी वैश्विक औसत से दोगुनी है।

युवा:

- आत्महत्या 15 से 39 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मृत्यु दर का मुख्य कारण है और काफी संख्या में युवा जीवन को मारता है।

सबसे आम तकनीक:

- फांसी लगाना आत्महत्या का सबसे आम तरीका है, इसके बाद आत्मदाह, ड्रग ओवरडोज़ और कीटनाशक विषाक्तता है।

अन्य घटक:

- आत्महत्या की संभावना अवसादग्रस्तता विकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों और शराब के सेवन विकारों से प्रभावित प्रतीत होती है।

आत्महत्या बनाम आत्महत्या के प्रयास:

- सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या का प्रयास करने की संभावना अधिक होती है, इसके विपरीत सच होने के बावजूद (सीडीसी)।
- दुनिया भर में आत्महत्या से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा भारत का योगदान है।
- भारत के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति वर्तमान में धीरे-धीरे विकसित की जा रही है।

आख़िर आत्महत्या क्या है?

- आत्महत्या इसे समाप्त करने के लक्ष्य के साथ अपने स्वयं के जीवन को जानबूझकर लेना है।
- आत्महत्या के प्रयास आत्महत्या करने के प्रयास हैं जो असफल होते हैं।

उपचार और उपचार:

- छोटे पैमाने पर हस्तक्षेप

सुरक्षा के लिए हो रही तैयारी:

- व्यक्तिगत सुरक्षा योजना को आत्मघाती विचारों और कार्यों को कम करने के लिए दिखाया गया है।

अनुवर्ती फोन कॉल:

- जोखिम वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की संभावना को कम करने के लिए अतिरिक्त स्क्रीनिंग, एक सुरक्षा योजना हस्तक्षेप, और उत्साहजनक फोन कॉल की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया है।

मनोचिकित्सा:

- संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) ग्राहक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए नए मुकाबला कौशल सीख सकते हैं।
- संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) लोगों को अपने विचार पैटर्न की पहचान करने और आत्मघाती विचार आने पर संभावित उपचारों पर विचार करने में सक्षम बनाती है।

- किशोर आत्मघाती व्यवहार (डीबीटी) को कम करने के लिए डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी को दिखाया गया है।
- भारत में आत्महत्या की कानूनी स्थिति:

धारा 309:

- यह नियम पहली बार 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था क्योंकि उस काल की मान्यताओं के कारण, जिन्होंने आत्मदाह या आत्महत्या के प्रयासों को राज्य और धर्म के खिलाफ अपराध के रूप में देखा था।
- आत्महत्या के प्रयास से बचे किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 309, "आत्महत्या करने का प्रयास" के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है या इस तरह से कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसा अपराध हो सकता है, उस पर जुर्माना, एक वर्ष तक की साधारण जेल की सजा, या दोनों हो सकते हैं।

धारा 309 के संबंध में:

- आम धारणा के विपरीत, यह खंड अभी भी आईपीसी में शामिल है और वर्तमान में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (एमएचसीए), 2017, जो जुलाई 2018 में लागू हुआ, ने धारा 309 आईपीसी के आवेदन के दायरे को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसने विशेष परिस्थितियों में आत्महत्या के प्रयासों की सजा को प्रतिबंधित कर दिया।
- इसका मतलब यह होगा कि एमएचसीए के प्रावधानों के तहत इसके उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध - इसके अंतिम उन्मूलन के विपरीत - अपर्याप्त हैं क्योंकि देश भर में पुलिस बलों द्वारा इसके उपयोग की रिपोर्टें अभी भी हैं।

भारत सरकार के कार्यों में शामिल हैं:

1982 का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज में सबसे वंचित और कमजोर समूहों पर जोर देने के साथ, निकट भविष्य में सभी की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हो।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017:

- 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को इस कानून से बदल दिया गया, जो मई 2018 में लागू हुआ। यह 2017 में एक कानून बन गया।
- भारतीय चिकित्सा पेशेवरों और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं के विशाल बहुमत की राहत के लिए, इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त कर दिया।
- इसके अतिरिक्त मानसिक बीमारियों के लिए डब्ल्यूएचओ वर्गीकरण भी शामिल थे।
- अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण घटक "उन्नत निर्देश" खंड था, जिसने मानसिक रोगों वाले व्यक्तियों को अपनी उपचार रणनीति और अधिवक्ता का चयन करने की अनुमति दी।

- ईसीटी के उपयोग को विनियमित करके और इसे बच्चों पर उपयोग करने के लिए अवैध बनाकर, इसने ऐसी नीतियां भी निर्धारित कीं जो अंततः भारतीय समाज में कलंक को मिटाने की ओर ले जाएंगी।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017:

- अधिनियम विकलांग लोगों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का विस्तार करने के लिए काम करता है और समाज में उनके सशक्तिकरण और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करता है। यह स्वीकार किया जाता है कि मानसिक बीमारी क्षीण होती है।

परियोजना मनोदर्पण:

- आत्मानबीर भारत अभियान पहल के हिस्से के रूप में छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोसामाजिक परामर्श प्राप्त होगा।

किरण सहायता:

- आत्महत्या की रोकथाम के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सहायता और संकट प्रबंधन की पेशकश करने की हेल्पलाइन की क्षमता है।

- हेल्पलाइन, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक पहचान, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन प्रदान करना है, की निगरानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) द्वारा की जाएगी।

गेटिंग सिस्टम के लिए मॉडल:

- द्वारपाल: द्वारपाल पहले से ही मौजूद हैं, अपराधियों के करीब हैं, और कैदियों की मदद करने की स्थिति में हैं।
- वे अन्य अपराधी हो सकते हैं जो जेल में समय काट रहे हैं या स्टाफ कर्मचारी जो मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता वाले कैदियों की पहचान करने और सहायता करने में कुशल हैं।
- द्वारपाल उन लोगों के बीच एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है जो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या मनोवैज्ञानिक समस्याएं और विशेषज्ञ देखभाल कर सकते हैं। आत्महत्या करने वाले दोषियों के लिए यह वास्तव में फायदेमंद है।

उद्देश्य:

- यह विचार मानता है कि अत्यधिक प्रतिभाशाली कैदियों को उन कैदियों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए जो आत्महत्या का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें परामर्श या अन्य सहायक सेवाओं के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पे:

- प्रस्ताव ने अपने दावे का समर्थन किया कि बैंगलोर जेल मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन का हवाला देते हुए 80% कैदियों को मानसिक बीमारी या पदार्थ उपयोग विकार था।

मैत्री मंडली:

- "बडी सिस्टम" अवधारणा, जो "दोस्तों" या "श्रोताओं" के रूप में जाने जाने वाले प्रशिक्षित दोषियों के माध्यम से सामाजिक सहायता प्रदान करती है, आत्मघाती कैदियों के कल्याण पर अनुकूल प्रभाव डालती है।
- मित्रों और रिश्तेदारों को बार-बार कॉल करने से समर्थन को बढ़ावा मिलेगा।

ई-मुलकत:

- राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जिसका उपयोग कार्यकर्ता, मित्र और कैदियों के परिवार पहले से ही दोषियों के साथ साक्षात्कार निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं।

प्रभार लेना:

- जो लोग अपने आप को प्रबंधित करने में असमर्थ हैं, वे एक मचान पद्धति से लाभान्वित हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे कमजोर समय के दौरान लगातार उपलब्ध और मौजूद होती है।
- रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की रोकथाम पर शोध करने और रोड मैप बनाने के लिए एक टास्क ग्रुप बनाया जाना चाहिए।
- आत्महत्याओं और आत्महत्या के प्रयासों पर हाल ही में, सटीक और भरोसेमंद डेटा की भी आवश्यकता है।
- कानून के कई मुद्दों में "आत्महत्या का प्रयास" वाक्यांश का समाधान।
- इसके अतिरिक्त, इसमें उन पहलों को शामिल किया गया है जिन्होंने कीटनाशकों तक पहुंच में कमी की है और परिणामस्वरूप, देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और कॉलेजिएट क्षेत्रों में आत्महत्या दर।
- मिशन मोड में एक कार्यक्रम शुरू करने का दृष्टिकोण देश में कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रभावी साबित हुआ है।
- समग्र मार्गदर्शन देने वाली राष्ट्रीय नीति को बदलते समय विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस देश में, घातक आत्महत्याओं का एक बड़ा प्रतिशत होता है। दर में 5% की कमी भी कई लोगों की जान बचाने से नहीं रोकेगी।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA